



अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
24 अकबर रोड नई दिल्ली-110011
मीडिया विभाग

पत्रकार वार्ता के मुख्य बिन्दु

सोमवार 16 जून, 2014 सायं-4.15

श्री शक्ति सिंह गोहिल और श्रीमती शोभा ओझा ने पत्रकारों को संबोधित किया ।

श्री शक्ति सिंह गोहिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और मोदी के लिए अच्छे दिन जरूर शुरू हो गए हैं, पर देशवासियों के बुरे दिन शुरू हुए हैं। सुनहरे सपने दिखाए थे कि हम सत्ता में आते ही सब कुछ कर देंगे आपके लिए और सोने का सूरज निकल आएगा। अब देशवासियों को किए हुए वायदे ना तो निभाए जाने वाले हैं और ना कर पाएंगे और इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ने के लिए आप ने भी देखा होगा-गोवा से शुरुआत की। इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है, कड़ा कुशासन रहा है, और आवाम को कड़वी गोलियां खाने के लिए और कड़े कदमों को सहन करने के लिए भी बोल दिया है। मैं स्वयं राज्य में वित्त मंत्री रहा हूँ और जब भी ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मैं किसी और से प्रमाण नहीं मांगता हूँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है। पर जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को कोस रहे हैं इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो कुछ ही महीने पहले गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार ने जो **Socio Economic Review** जो विधानसभा में पेश किया है, उसके अन्दर इस देश की हालत क्या है, इस बारे में चन्द शब्द लिखे हैं। प्रेस वार्ता के पश्चात इसकी प्रतिलिपि भी आपको दी जाएगी। इसमें लिखा है **Weaknesses in the major developed economies are at the root of the continued gloomy global economic environment and several European economies are already in recession. In fact, countries like India, China and Brazil have largely been responsible for stroking the engine of global economy during the year 2012.** यह 2012 की रिपोर्ट है। यह कहते हैं कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की हालत खराब रही, पर इस विश्व की अर्थव्यवस्था को जिसको आगे ले जाने का काम किन्हीं तीन देशों ने किया तो उसमें सबसे पहला भारत है, फिर चीन है और फिर ब्राजील है। जब वे लिख के कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है, सत्ता में आते ही कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रख रहा हूँ जिनको इसी **Socio Economic Review** में दिए गए हैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। यह जो आधार रेखा होती है वो राष्ट्र संघ द्वारा की जाती है क्योंकि इसका जिक्र इसमें किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि पूरे विश्व की **Gross Product** की जो विकास दर

है। यह आंकड़े मेरे नहीं हैं।

मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ औसत विकास दर जो यूपीए के दस वर्ष के शासनकाल में रहा वो 7.6 प्रतिशत रहा। एनडीए के पांच वर्ष के शासनकाल में औसत विकास दर 5.9 प्रतिशत रही। पूरी दुनिया में मंदी का दौर था फिर भी यूपीए सरकार में कुल अर्थव्यवस्था थी वो दो ट्रिलियन डालर कुल जीडीपी का— यही अर्थव्यवस्था एनडीए के शासनकाल में 500 विलियन डालर थी वो आज दो ट्रिलियन डालर हो गई है। यूपीए के शासनकाल में विदेशी रिजर्व 300 प्रतिशत बढ़ा है। 110 विलियन डालर से बढ़कर यूपीए के शासनकाल में 312 विलियन डालर हुआ है। प्रति व्यक्ति आय 24000 था एनडीए के शासनकाल में जो कि बढ़कर यूपीए के शासनकाल में 69000 प्रति व्यक्ति हो गया। 2004 में निर्यात 63 विलियन डालर था जो कि यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 313 विलियन डालर हो गया। पूरे विश्व में मंदी के बावजूद भी यह हमारा निर्यात था। बिजली का उत्पादन 113000 मेगावाट से बढ़कर 242000 मेगावाट हो गया। एफडीआई 17 प्रतिशत बढ़ी है 28 विलियन डालर। शिक्षा ऋण— एनडीए के शासनकाल में 46000 करोड़ का जो बढ़कर यूपीए के शासनकाल में 57,700 करोड़ हो गया। करेंट अकाउंट डैफिसिट (सीएडी) जो कि बहुत जरूरी होता है वो बहुत कम करके जीडीपी का 0.2 प्रतिशत 2013 से 2014 में हुआ है। यह कहते थे कि महंगाई तो यूपीए की देन है—महंगाई कम करने के नाम पर वोट बटोर लिए हैं। जो **Whole Sale Price Inflation** है इनके आने के बाद के सप्ताहों का वो बढ़कर 6.01 प्रतिशत है जो 5.2 प्रतिशत था यानि इनके बाद मुद्रास्फीति एक प्रतिशत बढ़ी है। तो यह जो बातें कही थीं और आज जो हो रही है और फिर बाद में यह कहना कि यह तो हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूपीए सरकार ने हालत इस प्रकार की करके रखी हुई है। केवल आपको एक छोटा सा चार्ट जो पूरी दुनिया का विकास 2010 से 2014 आप देख सकते हैं कि घट रहा है। भारत की विकास दर ऊपर ही जाती है। प्रति व्यक्ति आय भारत में दोनों रूप से दी गयी है मौजूदा कीमतों पर थी और पिछली कीमतों पर भी। अगर पूरे विश्व में मंदी के दौर में अगर कोई देश हो वो भारत है जिसने विकास किया है। आज वे प्रधानमंत्री जब राज्य में मुख्यमंत्री थे उनके 2012 से 2013 के **Socio Economic Review III, IV and V** पृष्ठ पर लगाए हैं, इसमें यूपीए सरकार की सकारात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की गयी है। और इस हालत में अच्छे दिन देश को नहीं दिखा पाने के सपने दिखाने के बाद आज जो उल्टी बात करते हैं। हमने 1991 में सरकार बनाई इस देश का सोना बाहर गिरवी पड़ा था। हमने कभी नहीं कहा कि कुछ लोग करके गए इसलिए हम ठीक नहीं कर पाते हैं। कुछ ही महीनों में इस देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया, बाहर पड़ा हुआ सोना, कांग्रेस की सरकार इस देश में वापिस लाई। हमने कभी दस साल नहीं मांगे, हमने कुछ ही महीनों में एकट किया। अब यह सपने दिखा के आए हैं, यह बात सही है कि हमारी इन बातों की मार्किटिंग सरकार के पैसों से या किसी एजेंसी के जरिए इस तरह से होना चाहिए था शायद हम नहीं कर पाए और कभी—कभी कुछ अच्छे लोग सच्चाई को ढूँढ के जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो झूठ बिक जाता है और सच

पिट भी जाता है। तो यह हालत भी हुई है पर ऐसा भी नहीं कि इस देश की जनता ने हमको नकार दिया है वोट प्रतिशत नहीं मिले हैं। यही भाजपा वाले मुझे भी कहते थे कि आपका को नकार दिया है, आपको कहने का अधिकार नहीं है। मोदी जी की पूरी कैबिनेट आने के बावजूद वहां के लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया है तो मुझे अब उन भाजपा वालों से भी यही कहना है कि कम से कम अब तो मेरी बात को मानो जब लोग मानते हैं।

श्रीमती शोभा ओझा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बहुत ही चिन्ता का विषय है। यूपी में देख रहे हैं कि रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। यूपी ही नहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी यूपी से अधिक चिन्ताजनक स्थिति है। अधिकारिक रिकार्ड के हिसाब से वहां रोज 12 मामले दर्ज होते हैं, पर उससे कहीं अधिक इस प्रकार के मामले वहां पर हैं। अभी पिछले दो दिन पहले खाण्डवा में एक आदिवासी महिला के साथ करीब नौ लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया जिसमें उसके पति भी शामिल थे। सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया बहुत ही शर्मनाक है कि उस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उसे उसके मासूम बच्चे के सामने उसे मूत्र पीने के लिए बाध्य किया गया जब उसने पानी मांगा, और इतना सब होने के बावजूद वहां की सरकार की तरफ से या भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं की तरफ से एक बयान तक नहीं आता है या कोई उस बात को लेकर दुःख या रोष व्यक्त नहीं करता। शनिवार को जब इस घटना की समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की एक मीटिंग लेने में स्वयं भोपाल में थी और हमने मीटिंग के बाद अपना रोष प्रकट करने के लिए गृहमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन का एलान किया, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का एक यह भी तरीका होता है, कि आप प्रदर्शन करें और प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से करना तय था, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस राजनीति के सिद्धांतों पर चलते हुए कभी भी प्रदर्शन को उग्र या अप्रजातांत्रिक बनाने की कोशिश नहीं करती है। महिला कांग्रेस की समस्त पदाधिकारियों ने जब गृहमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन चालू हुआ तो वहां बड़ी संख्या में पुलिस थी, महिला पुलिस कम और पुरुष पुलिस अधिक थी, जब कि हम घोषणा कर चुके थे और सूचित भी कर चुके थे कि महिलाओं द्वारा यह प्रदर्शन है। और फिर जब कि पुलिस ने महिलाओं के साथ झूमा-झटकी डंडे द्वारा उनको धक्का देना, गिराना, पानी फेंकने का इस्तेमाल करना और तमाम बदतमीजियां एवं बदसलूकियां महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ की गई, यह स्पष्ट रूप से वहां जो आवाज महिला कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में उठाई थी, उसको बन्द करने की एक कोशिश पुलिस के माध्यम से सरकार कर रही थी। एक ओर महिला अत्याचार तेजी से वहां से बढ़ रहा है उसके बाद उसी दिन एक और मामला सामने आया जिसमें एक चार वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला था जब कि बच्ची अस्पताल में भर्ती है, एक महिला जिस के पति कैदी थे वो थाने गई तो थाने में उसके साथ बलात्कार के साथ एक एमएमएस बनाया गया और हिम्मत देखिए मध्य प्रदेश पुलिस की, कि दो लाख रुपए उस महिला से मांगे गए ब्लैकमेल करने के लिए अन्यथा एमएमएस सार्वजनिक कर देंगे। तो पुलिस की क्या भूमिका है वहां, गृहमंत्री के

क्या बयान आते हैं, बाबू लाल गौर के क्या वक्तव्य आते हैं, किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। बाबू लाल गौर एवं आरएसएस के मुखिया तक वहां आकर मध्य प्रदेश में बलात्कार को लेकर बहुत ही हल्की बातें कर चुके हैं। यह सभी चीजें भाजपा की सोच को दर्शाती हैं। और दुःख होता है जब बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों पर भी भाजपा राजनीति करती है। जब यूपी में रेप होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो वो वहां की सरकार को बरखास्त करने की बात करती है। पर जब मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो तमाम भाजपा के नेता केंद्रीय गृहमंत्री तक चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल असुरिक्त हैं, कानून-व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, और जब कोई राजनीतिक पार्टी अपना प्रजातांत्रिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए विरोध करने जाती है तो उसको इस तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। मैं समझती हूँ कि यूपी और मध्य प्रदेश के हालत एक दूसरे से अलग कतई नहीं हैं और जिस प्रकार यूपी को लेकर भाजपा शोर मचा रही है तो उनके सभी नेताओं को कहना चाहूंगी कि यूपी में तो वो आवाज उठाए महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए खास तौर पर जो पार्टी शासन में है वो जरूर आवाज उठाए। पर साथ ही वो दूसरे प्रदेशों जैसे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश, वहां के महिला अत्याचार की अनदेखी ना करें। जब प्रधानमंत्री जी ने संसद में जीरो टौलरेंसी की बात कही थी महिला अत्याचार और बलात्कार को लेकर, और उनकी कलई खुल गई जब निहालचंद मेघवाल को आज तक उनको पद पर बनाए रखा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब वो पीड़िता उसका मामला दब चुका है और जब मामला बन्द हुआ था उससे पहले उस महिला के बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 Cr. PC में भी नहीं हुए थे। उसके पश्चात जब रिव्यू होने के लिए खुला है तो उस महिला को डराया वा धमकाया जा रहा है, मंत्री जी द्वारा कि वो केस वापिस ले। हम मांग करते हैं कि उस महिला को सरकार सुरक्षा दे और निहाल चंद को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो डर था हमें वो डर सच साबित हो रहा है जब उस पीड़िता ने यह कहा कि मंत्री जी उस पर दबाव बना रहे हैं, कहीं नौकरी का लालच दे रहे हैं, तो वहीं दबाव बना रहे हैं कि वो अपना केस वापिस ले, ले तो आज हमारी मांग यह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री जी केवल बोलें ना करके भी दिखाएं और तुरंत निहालचंद मेघवाल का इस्तीफा होना चाहिए जिससे कि वो पूरे केस पर कोई दबाव ना डाल पाएं और उस पीड़िता को न्याय मिल सके, यह हमारी मांग है। और साथ ही यह भी मांग है कि वो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार पर भी ध्यान दें। भाजपा के सभी नेताओं से हम यह कहना चाहते हैं और कड़े शब्दों में जो महिला कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, उसकी कड़े शब्दों में हम निन्दा करते हैं।

एक प्रश्न पर कि जब प्रवक्ता कह रही हैं कि यूपी में ऐसे मामले हो रहे हैं तो क्या उचित रहेगा कि यूपी को छोटे-छोटे राज्यों में बांट दिया जाए, श्रीमती ओझा ने कहा कि यह तो केंद्र सरकार का लुक आउट है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कुल मिला के यूपी उससे बड़ा

था पहले तब तो इतना महिला अत्याचार नहीं होता था वहां तो इसलिए कहना कि महिला अत्याचार प्रदेश के साईज से होता है, मैं मानने को तैयार नहीं।

एक अन्य प्रश्न पर कि जो प्रवक्ता आज आरोप लगा रहे हैं भाजपा को चुनाव के दौरान क्यों नहीं लगाए, श्री गोहिल ने कहा कि चुनाव के दौरान भी कहा था यह हमने। लेकिन आज भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री बन के यह कह रहे हैं कि मैं सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था खराब है। आप अपने राज्य में अपने बजट सत्र में कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है इसलिए आज हमारे लिए यह कहना जरूरी है।

एक अन्य प्रश्न पर कि बोर्डों और आयोगों में अथवा अनेक समितियों में पदाधिकारी को बदले जाने की चर्चा चल रही है, श्रीमती ओझा ने कहा कि मापदण्ड तो यही रहता है कि व्यक्ति अपना समयकाल पूरा करें क्योंकि जितने भी आयोग हैं उसमें एक निश्चित समयकाल रहता है, सामान्यता तो उनको पूरा करने देना चाहिए। सरकार को दबाव नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी अपने समयकाल से पहले अपना पद छोड़े।

एक अन्य प्रश्न पर कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं बताया कि वे हार के पश्चात क्या कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कोई चिन्तन शिविर होगा, आपके महाराष्ट्र के विधायक कह रहे हैं कि वहां के सीएम को हटाया जाए, आप कुछ अपनी पार्टी के बारे में भी बताएं, श्रीमती ओझा ने कहा कि आपके सवाल में ही उत्तर छिपा है कि अभी-अभी सब कुछ हुआ है, थोड़ा समय दीजिए।

हस्त/—
(टॉम वडक्कन)
मीडिया सचिव